भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3522

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को मुफ्त कोचिंग

3522. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोलः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आईआईटी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) कर्नाटक राज्य में विशेषकर चित्रदुर्ग संसदीय क्षेत्र में उक्त योजनाओं से लाभान्वित छात्रों की संख्या का जिला-वार, योजनावार एवं वर्षवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क): "अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना" सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा पैनलबद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए है, जिसमें 70:30 के अनुपात में स्लॉट आवंटित किए जाते हैं। इस योजना के लिए प्रति वर्ष 8 लाख रुपये तक की पारिवारिक आय वाले आवेदक पात्र हैं। प्रति वर्ष, इस योजना के तहत 3,500 स्लॉट उपलब्ध हैं। योजना के तहत आईआईटी-जेईई, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान की जाती है।

(ख): "अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना" के अंतर्गत कोचिंग पैनलबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जा रही है। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कर्नाटक में स्थित एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय ने इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। चूंकि "अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना" एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए लाभार्थियों का जिला-वार विवरण नहीं रखा जाता है।

*****